sector, the demand for wage employment generally increases during the lean agricultural season. In this regard, the Planning Commission have estimated that the total unemployment in the country at the end of March, 1995 was of the order of 18.69 million. However, separate break-up for rural and urban areas is not available. Further the Planning Commission has stated that according to 43rd round NSS (1987-88) the total unemployment was 14.35 million of which 66.78% was in rural areas.

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

479. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 से 1994-95 के दौरान प्रति वर्ष, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन एवं त्वरित जल प्रदाय कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी राशि जारी की गई;

(ख) इन राशियों में से राज्यवार कितनी राशि व्यय की गयी;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितने-कितने नल कूप और हैंडपंप स्थापित किए गए तथा हैंड पंप स्थापना के अलावा अन्य किन कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) इन वर्षों के दौरान भूगर्भ जल स्रोतों एवं परंपरागत पेयजल स्रोतों की सुरक्षा तथा विकासात्मक प्रयोजनों पर व्यय की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख) 1991-92 से 1994-95 तक ए०आर०डब्ल्यू एस०पी० सहित राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अन्तर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशियां और किया गया खर्च अनुपत्र में दिया गया है [देखिए परिशिष्ट 176, अनुपत्र संख्या 29] न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार खर्च अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 176, अनुपत्र संख्या 29]

(ग) और (घ) इस प्रकार की जानकारी को केन्द्रीय सरकार के स्तर पर मानीटर नहीं किया जाता है।

Sponge Iron Manufacturers' Association

480. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the Sponge Iron Manufacturers' Association has urged for reduction of customs duty on iron ore; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Sir.

(b) Representations received from the domestic steel producers/associations regarding change in customs duty are considered and remedial measures taken by Government wherever necessary.

Investment in Rural Development Sectors

481. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the total investment in the rural development sector during the 8th Plan;

(b) the investment in the IRDP during the same period;

(c) the percentage of families assisted under the IRDP which have overcome the poverty threshold during each of five years on the basis of the results of the concurrent evaluation; and

(d) the corresponding figure at the start of the Plan period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND

EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) The total investment in the rural development sector during the 8th plan of the order or Rs. 30,000 crores. Of this the investment in the IRDP during the 8th Plan period was of the order of Rs. 7384.71 crores.

(c) and (d) Based on the results of the Concurrent Evaluation of Integrated Rural Development Programme (IRDP) carried out by the Ministry of Rural Areas and Employment 16% of families assisted under IRDP were able to cross the poverty line of Rs. 6400/- during 1989. As per the preliminary results of Concurrent Evaluation of IRDP carried out during September, 1992 to February, 93, about 50% of assisted families could cross the poverty line of Rs. 6400/-.

Metalling of Katcha Road

482. SHRI RAM JETHMALANI: Will the Minister of RURAL AREAS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal/request/representation from the residents of Basot a nearby village, District Almora, for metalling of the Katcha Road from Mohan to Harara-Chauri Ghatti and Ghatti to Basot;

(b) if so, the action taken thereon alongwith the details thereof; and

(c) if not, by when the above stated work is expected to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Construction of rural roads is a State subject.

कास्टिक सोडा का उत्पादन करने वाली इकाईया

483. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कास्टिक सोडा का उत्पादन करने वाली कितनी इकाइयां हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) वर्तमान में कास्टिक सोडा सहित प्रमुख रसायनों के उत्पादन और उनकी खपत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कास्टिक सोडा की इकाइयों में इसका उत्पादन उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या अनेक रसायनों का उत्पादन भी उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनके उत्पादन में कमी के कारण ऐसी इकाइयों के कार्य-निष्पादन पर क्या असर पड़ा है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) (क) से (च) देश में 37 कास्टिक सोडा उत्पादन इकाइयों की कुल अधि स्थापित क्षमता 13.11 लाख टन है। वर्ष 1994-95 में क्षमता उपयोगिता 88.17 प्रतिशत थी जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक थी उर्जा बहुल कास्टिक सोडा उद्योग में क्षमता का अच्छा उपयोग है और यह मांग जरूरतें पूरी करता है। कुछ आयातित रसायनों का उत्पादन वर्ष 1994-95 में निम्न प्रकार था:

क्रम सं॰	रसायन का नाम	1994-95 में उत्पादन (मात्रा हजार टनों में)
1.	कास्टिक सोडा	1156.
2.	सोडा ऐस	1408.6
3.	कैलसियम कारबाइड	97.4
4.	ऐसटिक ऐसिड	177.4
5.	ऐसोटिक्स ऐसिड	90.0